आकाशवाणी गोरखपुर
प्रादेशिक समाचार

दिनांक–30 जनवरी 2026 **7:20 AM**

पहले मुख्य समाचार।

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में तीस प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। प्रदेश के लगभग पन्द्रह लाख शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा।
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में प्रस्तुत किया आर्थिक सर्वेक्षण दो हजार पचीस छब्बीस। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा–चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में निरंतर प्रगति को दर्शाती है यह समीक्षा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए समानता संबंधी नियमों पर लगाई रोक। प्रतिष्ठित न्यायविदों की समिति द्वारा नियमों की समीक्षा का दिया सुझाव।
- संपति पंजीकरण में एक फरवरी से लागू होगा आधार प्रमाणीकरण।

****

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल बत्तीस प्रस्ताव आए, जिनमें तीस को स्वीकृति मिल गई । बैठक में आगामी बजट सत्र को भी मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नौ फरवरी से बजट सत्र शुरु होगा और ग्यारह फरवरी को बजट पेश किया जाएगा।

9 तारीख को महामहिम श्री राजपाल जी का अभिभाषण होगा और उसके बाद 10 तारीख को क्योंकि एक हमारे दो माननीय सदस्यों का निधन हो गया इसलिए उनके निधन पर श्री शोक व्यक्त किया जाएगा और 11 तारीख को बजट आएगा वर्ष 26–27 का।

प्रदेश सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़े लाखों कर्मियों को बड़ी राहत दी है। एक रिपोर्ट–

कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मियों और उनके आश्रित परिवारों को सरकारी के साथ–साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष इसकी घोषणा की थी जिसपर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इससे बेसिक व माध्यमिक शिक्षा से जुडे लगभग पन्द्रह लाख शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी लाभान्वित होगें। इलाज की दरें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय मानकों के अनुसार होंगी। समाचार कक्ष से प्रेम चन्द्र गुप्ता।

कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि सरकार के फैसले से बेसिक शिक्षा परिषद के करीब बारह लाख शिक्षक और कर्मी लाभान्वित होंगे।

कुल मिलाकर के 11,95,391 हमारे जो प्रदेश में शिक्षक हैं, इनके लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, इसको माननीय मंत्री परिषद के द्वारा सहमति मिली है। इसमें एक व्यवस्था यह जोड़ी गई है और इसका जो कुल लागत है, वह लागत भी आएगी इसमें 358.61 करोड़ की।

बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को वेरिफिकेशन के बाद योजना का लाभ मिलेगा। वेरिफिकेशन के लिए जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में शहरी पुनर्विकास नीति दो हजार छब्बीस को भी मंजूरी दी गई। सीएम फेलोशिप वाले अभ्यर्थियों को राज्य लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली भर्तियों में आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का भी फैसला लिया गया। कैबिनेट ने पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास से जुड़े प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी।

****

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक समीक्षा को देश का "रिफार्म एक्सप्रेस" बताया है। श्री मोदी ने कहा कि यह समीक्षा चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में निरंतर प्रगति को दर्शाती है। यह मजबूत व्यापक आर्थिक आधारभूत सिद्धांतों, सतत विकास गति और राष्ट्र के निर्माण में नवाचार, उद्यमिता और अवसंरचना की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक समीक्षा, समावेशी विकास के महत्व पर बल देती है। इसमें किसानों, लघु और मध्यम उद्यमों, युवा रोजगार और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा कल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। एक रिपोर्ट–

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर सात दशमलव चार प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें घरेलू मांग का महत्वपूर्ण योगदान है। निजी उपभोग और पूंजी निर्माण से वृद्धि को समर्थन मिल रहा है, जबकि आपूर्ति पक्ष में सेवाओं का योगदान प्रमुख बना हुआ है। विनिर्माण गतिविधि मजबूत हुई है और कृषि क्षेत्र ने स्थिरता प्रदान की है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का हाल का आर्थिक प्रदर्शन दर्शाता है कि वैश्विक उथल–पुथल के बावजूद व्यापक आर्थिक स्थिरता और वृद्धि को बनाए रखा जा सकता है। अनुकूल मानसून परिस्थितियों के सहयोग से वित्त वर्ष 2025–26 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि तीन दशमलव एक प्रतिशत रहने का

अनुमान है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित कुल महंगाई दर घटकर एक दशमलव सात प्रतिशत रह गई है, जिसका मुख्य कारण सब्जियों और दालों की कीमतों में सुधार रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार, मुद्रास्फीति की स्थिति अनुकूल बने रहने का अनुमान है। आनंद और भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में नए उत्तर प्रदेश ने वित्तीय अनुशासन, संतुलित बजट प्रबंधन और प्रभावी शासन के माध्यम से वर्ष दो हजार पच्चीस–छब्बीस में महंगाई नियंत्रण और आर्थिक सुदृढ़ता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आर्थिक सर्वेक्षण दो हजार पच्चीस–छब्बीस के अनुसार यह उपलब्धियां राज्य की मजबूत अर्थव्यवस्था और लोक–हितकारी नीतियों का स्पष्ट प्रमाण हैं। जीएसडीपी के लगभग दो दशमल छः प्रतिशत के राजस्व अधिशेष के साथ राज्य ने आम जनता के हितों की प्रभावी रूप से रक्षा सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुदृढ़ निगरानी, आधुनिक ट्रैकिंग व्यवस्था और पारदर्शी आपूर्ति शृंखला के माध्यम से खाद्यान्न की निर्बाध उपलब्धता और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित हुई है, जिससे गरीब, किसान और श्रमिक वर्ग को व्यापक लाभ मिला है।

****

सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन नियम–दो हजार छब्बीस को स्थगित करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट–

न्यायालय ने नियमों पर कुछ आपत्तियां व्यक्त कीं, जिन्हें सामान्य वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण बताया गया। न्यायालय ने सुझाव दिया कि प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति द्वारा नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ दो हजार छब्बीस के विनियमों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली तीन रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने आदेश दिया कि इस बीच वर्ष दो हजार बारह के यूजीसी विनियम लागू रहेंगे। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।

****

प्रदेश के स्टाम्प और पंजीयन राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कल लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आगामी एक फरवरी से संपत्ति पंजीकरण में आधार प्रमाणीकरण लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।

अभी 1 तारीख से उत्तर प्रदेश में हर रजिस्ट्री में आधार के बेस पर चेक किया जाएगा। उसके अंगूठा लगा करके हम क्रॉस चेक कराएंगे। उसके क्रॉस चेक में जो आधार पर उसके पूरी डाटा है इकट्ठा उसका नाम, लोकेशन, उसका निशान सब कुछ उसमें आ जाएगा तब रजिस्ट्री हम लोग करेंगे।

****

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के तत्वावधान में कल से गोरखपुर में दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के सदस्य अलकेश शर्मा ने सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करते हुए अपने सम्बोधन में डिजिटल प्रौद्योगिकियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा नवाचार आधारित अनुसंधान की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये तत्व समावेशी विकास को गति देने और भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

****

दो दिवसीय दौरे पर भारत आईं थाईलैंड की रानी चखुन सिनिनात वांगवजीरापकडी ने कल भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल मुकुट बंधन चौत्य की परिक्रमा कर के पूजा अर्चना की।

****